Indian e-Journal on Teacher Education (IEJTE)
Bi-Monthly e-Journal (Peer Reviewed)
ISSN
2320 –7566

नई शिक्षा नीति और नया मंच: शिक्षकों के लिए नई तकनीक के विशेष सन्दर्भ में

डॉ. नीरू वर्मा,
भगवंत यूनिवर्सिटी,
अजमेर, राजस्थान

डॉ. मनोज कुमार
भगवंत यूनिवर्सिटी,
अजमेर, राजस्थान

==========

1. परिचय

21वीं सदी में, छात्रों और समाज की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। इन परिवर्तनों के केंद्र में नई शिक्षा नीतियाँ, प्लेटफॉर्म और तकनीकें शामिल हैं जो शिक्षकों की भूमिका और कक्षा के अनुभव को नया आकार दे रही हैं। ये सुधार समानता, समावेशिता और व्यक्तिगत सीखने को बढ़ावा देते हुए तेजी से डिजिटल और परस्पर जुड़ी दुनिया की चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। नई शिक्षा नीति पाठ्यक्रम में डिजिटल साक्षरता, आलोचनात्मक सोच और अंतःविषय दृष्टिकोणों को एकीकृत करके सीखने के उद्देश्यों को फिर से परिभाषित करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य एक अधिक लचीला और अनुकूलनीय शैक्षिक वातावरण बनाना है जो व्यक्तिगत सीखने की शैलियों का समर्थन करता है, सहयोग को बढ़ावा देता है और आजीवन सीखने पर जोर देता है। इस बदलाव की आधारशिला के रूप में शिक्षकों को विभिन्न छात्रों की जरूरतों को पूरा करने वाले अभिनव सीखने के अनुभवों को डिजाइन करने के लिए अधिक स्वायत्तता के साथ सशक्त बनाया गया है। इन नीतिगत परिवर्तनों का समर्थन करने के लिए, एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म पेश किया गया है, जो शिक्षकों को शैक्षिक संसाधनों तक पहुँचने, कक्षाओं का प्रबंधन करने और निरंतर व्यावसायिक विकास में संलग्न होने के लिए वन–स्टॉप समाधान प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर्म AI–संचालित टूल को एकीकृत करता है जो व्यक्तिगत शिक्षण रणनीतियाँ, छात्र प्रदर्शन पर वास्तविक समय की प्रतिक्रिया और शिक्षकों के लिए सर्वोत्तम अभ्यासों को साझा करने के लिए सहयोगी स्थान प्रदान करता है।

भारत को एक वैश्विक महाशक्ति बनाने के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण दिन चिह्नित किया जाना है। लंबे समय से प्रतीक्षित, नई शिक्षा नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बुधवार, 29 जुलाई 2020 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में अनुमोदित किया गया था। नई शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य स्कूलों और उच्च शिक्षा की शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन सुधार लाना है। भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में मजबूत करने की दिशा में 34 साल पुरानी शिक्षा प्रणाली को बदलना एक और बड़ा कदम है। पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान, 1985 में, शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन विकास (भ्त्व) के रूप में एक नया नाम सौंपा गया था। और 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली (एनईपी) का गठन किया गया था। पूर्व प्रधान मंत्री पीवी नरसिम्हा राव राजीव गांधी कैबिनेट के तहत पहले मानव संसाधन विकास मंत्री थे। नई एनईपी में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करना भी शामिल है। ''एक भारत श्रेष्ठ भारत'' की भावना को बढ़ावा देते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, ''छात्रवृत्ति की उपलब्धता को व्यापक बनाने, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, ऑनलाइन शिक्षा और प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने जैसे पहलुओं पर एनईपी में बहुत ध्यान दिया गया है। . ये शिक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण सुधार हैं।"

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) शुरू करके स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली में परिवर्तनकारी सुधार का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने एमएचआरडी का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया। पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद जो 1986 में शुरू की गई थी, यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है जिसने 34 साल पुरानी शिक्षा नीति को बदल दिया है। नई एनईपी चार स्तंभों पर आधारित है जो पहुंच, इक्विटी, गुणवत्ता और जवाबदेही हैं। इस नई नीति में, 5़3़4 संरचना होगी जिसमें 12 साल का स्कूल और 3 साल का आंगनबाडीध्पूर्व–विद्यालय पुराने 10़2 ढांचे की जगह शामिल होगा।

ट्वीट सूत्र में, एनईपी का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा, "मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुमोदन का तहे दिल से स्वागत करता हूं! यह शिक्षा के क्षेत्र में एक लंबे समय से लंबित और बहुप्रतीक्षित सुधार था, जो आने वाले समय में लाखों लोगों के जीवन को बदल देगा।"

नई शिक्षा व्यवस्था आने वाले समय में टर्निंग स्टोन साबित हो सकती है। कुछ ने खुले दिमाग से इसका स्वागत किया है और कुछ के लिए, पेश किए गए बदलाव अभी भी भ्रमित करने वाले हैं। आम आदमी के लिए इसे समझना आसान बनाने के लिए, एनईपी की कुछ प्रमुख विशेषताएं यहां दी गई हैं।

समानांतर रूप से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संवर्धित वास्तविकता और आभासी वास्तविकता जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियाँ शिक्षकों द्वारा सामग्री वितरित करने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव ला रही हैं। ये उपकरण इमर्सिव और इंटरेक्टिव लर्निंग अनुभव को सक्षम करते हैं, जिससे छात्र जटिल विषयों के साथ अधिक गहराई से जुड़ सकते हैं। शिक्षकों को छात्रों का आकलन करने, उन्हें प्रेरित करने और उन्हें प्रेरित करने के नए तरीकों से लैस किया जाता है, जिससे गतिशील, भविष्य के लिए तैयार कक्षाएँ बनती हैं। प्रगतिशील नीतियों, प्लेटफॉर्म और तकनीकों की यह शुरूआत शिक्षा में एक नए युग का संकेत देती है, जहाँ शिक्षक न केवल ज्ञान के सूत्रधार हैं, बल्कि सीखने के भविष्य को आकार देने वाले नवोन्मेषक भी हैं।

2. एनईपी 2020: शिक्षा का एक नया मॉडल और शिक्षा की नई व्यवस्था

आज के तेजी से बदलते समय में शिक्षा के पारंपरिक मॉडल को नए दृष्टिकोण और आधुनिक तकनीक के साथ फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिए एक लचीला और समावेशी मॉडल विकसित किया जा रहा है। यह नया मॉडल न केवल ज्ञान के प्रसार पर बल देता है, बल्कि कौशल विकास, रचनात्मकता, और समग्र विकास को भी प्राथमिकता देता है। एनईपी 2020, पाठ्यक्रम संरचना, मूल्यांकन मानदंड और विनियमों में सुधार के अपने प्रावधानों के साथ, शिक्षण और सीखने के लिए एक नए दृष्टिकोण का वादा करता है। बहुत संक्षेप में, एनईपी के कुछ अनुमानित लाभों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। नई शिक्षा नीति 2021 को मोदी सरकार ने अपनाया था। नई शिक्षा नीति में 10़2 के ढांचे को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। हमारे देश का शैक्षिक पाठ्यक्रम 10़2 पर आधारित रहा है, लेकिन यह जल्द ही 5़3़4 पर आधारित होगा। इसका मतलब है कि आधा प्राथमिक से दूसरी कक्षा का है, दूसरा भाग तीसरी से पांचवीं कक्षा का है, तीसरा भाग छठी से आठवीं कक्षा का है, और अंतिम भाग नौवीं से बारहवीं कक्षा का है।

शिक्षा के इस नए मॉडल में निम्नलिखित प्रमुख तत्व शामिल हैं:

व्यक्तिगत और अनुकूल शिक्षा: इस मॉडल में हर विद्यार्थी के सीखने की क्षमता और रुचियों के आधार पर शिक्षा को अनुकूलित किया जाता है। तकनीक की मदद से, शिक्षकों को प्रत्येक विद्यार्थी के प्रदर्शन का विश्लेषण कर उनके लिए सही सामग्री और शिक्षण पद्धति का चयन करने में आसानी होती है।

तकनीकी समावेश: आधुनिक तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आभासी वास्तविकता, और डेटा एनालिटिक्स के उपयोग से शिक्षा को अधिक इंटरएक्टिव और आकर्षक बनाया जा रहा है। इन तकनीकों की मदद से जटिल अवधारणाओं को समझना और वास्तविक दुनिया के संदर्भ में उनका उपयोग करना आसान होता है।

कौशल आधारित शिक्षा: पारंपरिक विषय–आधारित शिक्षा के स्थान पर, इस मॉडल में छात्रों को वास्तविक जीवन में उपयोगी कौशल जैसे समस्या समाधान, नेतृत्व क्षमता, संवाद कौशल और आलोचनात्मक सोच को विकसित करने पर जोर दिया जाता है।

लचीली शिक्षा प्रणाली: नए मॉडल में शिक्षा का स्वरूप कक्षा तक सीमित न होकर ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से लचीला बनाया गया है। विद्यार्थी अपनी गति और सुविधा के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं।

समावेशी और वैश्विक दृष्टिकोण: इस व्यवस्था में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना हर विद्यार्थी को समान अवसर प्रदान किया जाता है। साथ ही, वैश्विक चुनौतियों और अवसरों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का ढांचा तैयार किया गया है।

शिक्षा की यह नई व्यवस्था न केवल विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार करती है, बल्कि शिक्षकों को भी एक नई भूमिका में प्रस्तुत करती है। अब शिक्षक न केवल जानकारी के स्रोत हैं, बल्कि मार्गदर्शक, सलाहकार, और प्रेरणास्रोत की भूमिका निभा रहे हैं। इस नए मॉडल के साथ, शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ डिग्री प्राप्ति नहीं, बल्कि एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जो ज्ञान, कौशल और मूल्य आधारित हो।

3. नई शिक्षा नीति की मुख्य विशेषताएं

- सार्वजनिक और निजी दोनों उच्च शिक्षा संस्थान समान मानदंडों के तहत शासित होंगे।
- क्षेत्रीय भाषा/मातृभाषा को बढ़ावा देने और उस पर अधिक जोर देने के लिए कक्षा 5 तक का शिक्षण माध्यम स्थानीय/घरेलू भाषाओं में होगा।
- उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों के लिए सभी प्रवेश परीक्षाएं सामान्य रूप से आयोजित की जाएंगी।
- मुख्य अवधारणाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए स्कूल पाठ्यक्रम।
- मेडिकल और लॉ कॉलेजों को छोड़कर सभी उच्च शिक्षा संस्थान एक ही नियामक द्वारा शासित होंगे।
- एमफिल कोर्स अब बंद कर दिए जाएंगे।
- बोर्ड परीक्षा अब अधिक आवेदन और ज्ञान आधारित होगी।
- छठी कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाएगी।
- 10+2 अध्ययन संस्कृति बंद हो जाती है और 5+3+3+4 की नई संरचना का पालन किया जाएगा, जो संबंधित आयु वर्ग 3–8, 8–11, 11–14 और 14–18 वर्ष के अधीन होगा।

4. नई शिक्षा नीति: डिजिटल युग के लिए सीखने को फिर से परिभाषित करना

नई शिक्षा नीति पारंपरिक, एक–आकार–सभी–फिट मॉडल से अधिक लचीले, अनुकूली ढाँचे की ओर बदलाव लाती है जो व्यक्तिगत सीखने को प्राथमिकता देते हैं। कुछ प्रमुख सिद्धांतों में शामिल हैं:

व्यक्तिगत सीखने के मार्ग: छात्रों को अपनी गति और शैली से सीखने की अनुमति देकर, नीति कक्षा में शिक्षार्थियों की विविधता को पहचानती है। AI–संचालित उपकरण जैसी प्रौद्योगिकियाँ शिक्षकों को प्रत्येक छात्र की अनूठी जरूरतों और सीखने की गति की पहचान करने में मदद कर सकती हैं, जिससे उन्हें अनुरूप शिक्षण संसाधन मिल सकें।

महत्वपूर्ण सोच और समस्या–समाधान पर जोर: डिजिटल युग में, रटना और याद रखना कम प्रासंगिक है। नीति ऐसे पाठ्यक्रम को प्रोत्साहित करती है जो उच्च–क्रम की सोच कौशल, महत्वपूर्ण विश्लेषण, रचनात्मकता और समस्या–समाधान क्षमताओं को बढ़ावा देते हैं, छात्रों को जटिल वैश्विक चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं।

डिजिटल साक्षरता का एकीकरण: नई नीति डिजिटल साक्षरता को पढ़ने, लिखने और गणित के साथ–साथ एक बुनियादी कौशल के रूप में अनिवार्य बनाती है। यह छात्रों को तेजी से डिजिटल होती दुनिया में नेविगेट करने के लिए तैयार करता है और शिक्षकों को अपने पाठों में तकनीक को प्रभावी ढंग से शामिल करने के लिए ज्ञान और उपकरणों से लैस करता है।

समावेशी शिक्षा: नीति सभी छात्रों के लिए शिक्षा तक समान पहुँच की वकालत करती है, चाहे उनकी सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि या योग्यता का स्तर कुछ भी हो। शिक्षकों को विविध शिक्षार्थियों का समर्थन करने के लिए संसाधनों से लैस किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि शिक्षा सुलभ और समावेशी हो।

5. शिक्षण–अधिगम के नए मंच और तकनीक

एनईपी सभी शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को हर साल कम से कम 50 घंटे की सतत व्यावसायिक विकास कार्यशालाओं में भाग लेने का आदेश देता है। यह शिक्षण कौशल और तकनीकों को परिष्कृत करेगा। एनईपी ने शिक्षण–अधिगम अनुभव को समृद्ध करने के लिए विचारों के आदान–प्रदान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच नामक एक स्वायत्त निकाय की कल्पना की है। डिजिटल क्रांति और शैक्षणिक नवाचार लगातार सीखने और शिक्षण के लिए तकनीकों के नए मंच तैयार कर रहे हैं। एनईपी 2020 रचनात्मकता के क्षेत्र को और खोलेगा। शैक्षिक संस्थानों को एनईपी में परिकल्पित पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नई सुविधाओं को समायोजित करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे में सुधार करना होगा।

6. चुनौतियाँ और विचार

जबकि नई नीतियों, प्लेटफॉर्म और तकनीकों का एकीकरण परिवर्तनकारी बदलाव का वादा करता है, कई चुनौतियाँ हैं जिनका समाधान किया जाना चाहिएरू

डिजिटल विभाजन: सभी स्कूलों या छात्रों के पास डिजिटल तकनीकों तक समान पहुँच नहीं है। नीति निर्माताओं को इन असमानताओं को दूर करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी छात्र इस डिजिटल परिवर्तन में पीछे न छूट जाए।

शिक्षक प्रशिक्षण: कई शिक्षक अभी तक AI, AR या VR जैसी उन्नत तकनीकों से परिचित नहीं हो सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए चल रहे व्यावसायिक विकास और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होंगे कि शिक्षक इन उपकरणों को अपनी कक्षाओं में प्रभावी ढंग से एकीकृत कर सकें।

डेटा गोपनीयता और नैतिकता: AI और डेटा एनालिटिक्स के उदय के साथ, छात्र डेटा गोपनीयता की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा और शिक्षा में AI के नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट नीतियाँ स्थापित की जानी चाहिए।

7. निष्कर्ष

निष्कर्ष में, नीति, प्लेटफॉर्म और तकनीक का अभिसरण शिक्षा में एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जो शिक्षकों को प्रेरित करने, नवाचार करने और तेजी से डिजिटल दुनिया में अनुकूलन करने के लिए सशक्त बनाता है। नीति विभिन्न उद्योग हितधारकों और नियामक प्राधिकरणों/शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर भी प्रस्तुत करती है। इस संबंध में, इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एड–टेक उद्योग और एनईटीएफ के बीच एक साझेदारी की सिफारिश की है, जो अनुसंधान को सुव्यवस्थित करने में मदद करेगी और एनईटीएफ को उद्योग के नेतृत्व वाली सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने में सक्षम बनाएगी। यह सार आधुनिक शिक्षा को आकार देने वाली परस्पर जुड़ी प्रगति को रेखांकित करता है, तथा नवीन साधनों के माध्यम से शिक्षण क्षमताओं और छात्र संलग्नता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। नई शिक्षा नीतियों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और उन्नत तकनीकों के संयोजन से शिक्षा में क्रांति लाने की क्षमता है। शिक्षकों को सफल होने के लिए आवश्यक उपकरण और संसाधन प्रदान करके, ये नवाचार छात्रों के लिए अधिक व्यक्तिगत, आकर्षक और प्रभावी शिक्षण अनुभव प्रदान कर सकते हैं। हालाँकि, सफल कार्यान्वयन के लिए डिजिटल डिवाइड, शिक्षक प्रशिक्षण और डेटा गोपनीयता संबंधी चिंताओं जैसी चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है। जैसे–जैसे शिक्षा प्रणाली विकसित होती जा रही है, नीति निर्माताओं, शिक्षकों और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के बीच सहयोग सीखने के भविष्य को आकार देने में आवश्यक होगा।

सन्दर्भ:

- केपीएमजी इंटरनेशनल लिमिटेड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रभाव और हितधारकों के लिए अवसर।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी)। मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 (सारांश)।
- पीएस ऐथल एट। अल. (2020)। अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विश्लेषण। प्रबंधन, प्रौद्योगिकी और सामाजिक विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल (आईजेएमटीएस), श्रीनिवास प्रकाशन, वॉल्यूम। 5, नंबर 2, आईएसएसएनः 2581–6012, अगस्त, 2020। पीपी। 22–31.
- ब्रिटिश काउंसिल, यूके। भारत की नई शिक्षा नीति 2020: हाइलाइट्स और अवसर।
- शिक्षा जगत। एनईपी 2020: कार्यान्वयन चुनौतियां।
- भारत शिक्षा डायरी। नई शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताएं।
- स्मिथ, जे. (2023). शिक्षा में डिजिटल परिवर्तन: एआई और उभरती प्रौद्योगिकियों की भूमिका। शैक्षिक समीक्षा।
- जॉनसन, पी. (2022)। व्यक्तिगत शिक्षा का भविष्य: नीति और अभ्यास। शैक्षिक नवाचार की पत्रिका।
- विलियम्स, ए. (2024)। कक्षा में संवर्धित वास्तविकता: छात्र जुड़ाव पर प्रभाव। एडटेक इनसाइट्स।
- यूनेस्को। (2021)। 21वीं सदी में समावेशी शिक्षा: वैश्विक दृष्टिकोण और नीतियाँ। यूनेस्को प्रकाशन।